from plant to plant depending on a variety of factors including vintage of the plant, feed-stock, financing pattern, location etc. The landed cost of imported fertilizer also is liable to vary from contfact to contract. Currently, however, the landed cost of imported urea is higher than its average retention price for domestically produced urea.

Retrenchment of daily wage employees of D. A. V. P.

*208. SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government have received any representation from daily wage employees of D.A.V.P. against their retrenchment;

(b) if so, what action has been taken by Government thereon;

(c) the number of daily wage employees retrenched from service in D.A.V.P.; and

(d) the number of them who have been absorbed in regular service since 1989 in the DAVP?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI GIRIJA VYAS): (a) Yes, Sir. A few representations were received from some Daily Wages of DAVP against their discontinuation.

(b) Some Daily Wagers who have been discontinued are being kept on a penal in order of seniority to be engaged whenever need arises, in accordance with the advice of DP&T.

(c) 11 daily wagers who were juniormost were disengaged since 1989 as per requirement.

(d) 38 daily wagers have been regularised since 1989 in DAVP.

"उद्योगरहित जिलों" में उद्योगों का खोला जाना

*209. **श्री अजीत जोग :**

कुमारी आलिया :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नयी औद्योगिक नीति के अधीन "उद्योग रहित जिलों" और पिछड़े जिलों में उद्योगों को खोलने की योजनाएं बन्द कर दी गयी हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए दी जा रही राजसहायता को समाप्त किये जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार देश के पिछड़े अविकसित और आदिवासी क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए नई पहल करने का विचार रखती है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना, 1971 को 30.9.1988 से समाप्त कर दिया गया था। "उद्योग रहित जिलों" में मूलभूत सुविधाओं के विकासार्थ केन्द्रीय सहायता की जो योजना 1983 में चालू की गई थी उसे जून, 1988 में बंदकर दिया गया था किन्तु योजना के अधीन जो वायदे किये जा चुके थे उन पर अमल करने का काम जारी रहा।

पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए "विकास केन्द्रों" की नयी योजना जून 1988 में चालू की गयी थी जिसके अधीन 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में 70 विकास केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन विकास केन्द्रों में 25-30